दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 3811/2019

स्वतंत्र विचार ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विक्रम श्रीवास्तव और सुश्री शालू, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री मोनिका अरोड़ा, सी. जी. एस. सी. के साथ श्री यश त्यागी और श्री सुभ्रोदीप, यू. ओ. आई. के लिए के अधिवक्तागण।

निर्णय तिथि: 03 मई, 2023

कोरमः
माननीय न्यायाधीश श्री मनमोहन
माननीय न्यायाधीश श्री सौरभ बनर्जी

निर्णय

न्या. मनमोहन: (मौखिक)

1. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई हैः

"क) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, या इस तरह के अन्य समान रिट, घोषणा की प्रकृति में, धारा 198 (6) को

लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के साथ असंगत सीमा तक असंवैधानिक और अधिकारातीत घोषित करना और रद्द करने के लिए उत्तरदायी होना; और

ख) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना या घोषणा की रिट कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 21 के साथ पठित धारा 19 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत किए जा रहे अपराध की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है जो धारा 198 (3) के साथ पठित धारा 198 (1) के तहत लगाए जा रहे प्रतिबंधों को अध्यारोही करता है; और

ग) 198 (3) के तहत 'व्यक्ति' की परिभाषा को व्यापक बनाने के लिए उत्प्रेषण या घोषणा की रिट की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जो अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की ओर से शिकायत करने का इरादा रखता है, जिसमें विशेष रूप से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत प्रदान की गई चाइल्डलाइन (1098), बाल कल्याण समिति और अन्य एजेंसियों को शामिल करने के लिए, जिससे उन्हें जिम्मेदारी के साथ सशक्त बन जाए।

घ) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 3(3) के उपबंधों के अनुरूप वैवाहिक बलात्कार की नाबालिग पीड़िताओं को 20 वर्ष की आयु तक शिकायत दर्ज के लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए 198(6) दंड संहिता, 1973 के उपबंधों के सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण संशोधन के लिए उत्प्रेषण या घोषणा रिट की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निदेश जारी करना।

ङ) ऐसे अन्य आदेश या आदेशों और निर्देश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ न्याय के हित में भी उचित और सही समझे; ।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से तर्क</u>

2. शुरुआत में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता संतुष्ट होगा यदि इस आशय की घोषणा की जाती है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 ('पॉक्सो अधिनियम') की धारा 21 के साथ पठित धारा 19 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं. प्र. सं.) की धारा 198(3) के साथ पठित धारा 198 (1) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का अध्यारोही करता है और यदि नाबालिग पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज करने की सीमा को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि वह बालिग होने के दो साल पूरे नहीं कर लेती है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दं. प्र. सं. की धारा 198(6) वैवाहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़कियों के अधिकारों के संरक्षण में एक बाधा है क्योंकि यह ऐसे नाबालिग पीड़िताओं के कानूनी उपचार के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। वह निवेदन किया है कि जबकि मौलिक विधि किसी भी प्रकार के वर्गीकरण या भेदभाव का प्रावधान नहीं करता है, प्रक्रियात्मक कानून वैवाहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के साथ भेदभाव करना जारी रखता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 198 के प्रासंगिक भाग पर भरोसा किया गया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

*"**198. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन।** (1) कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 20 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के:*

बशर्ते कि-

(क) जहां ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है, या मूर्ख या अज्ञानी है, या बीमारी या दुर्बलता से शिकायत करने में असमर्थ है, या ऐसी महिला है, जिसे स्थानीय रीति-रिवाजों और शिष्टाचार के अनुसार, सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से, उसके या उसकी ओर से शिकायत कर सकता है।;

XXX XXX XXX

(3) जब किसी भी मामले में उप-धारा (1) के सम्बन्ध में परंतुक के खंड (क) के तहत आते हैं, तो अठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या पागल की ओर से शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाने की मांग की जाती है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नाबालिग या पागल व्यक्ति के अभिभावक होने के लिए नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय संतुष्ट है कि एक अभिभावक नियुक्त या घोषित किया गया है, न्यायालय, अनुमति के लिए आवेदन को अनुमति देने से पहले, ऐसे अभिभावक को नोटिस देगा और उसे सुनवाई का उचित अवसर देगा। ।

XXX XXX XXX

(6) कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जहां ऐसे अपराध में किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ, पत्नी [अठारह वर्ष] से कम आयु का यौन

संभोग करता है, यदि अपराध किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि युवा नाबालिग लड़कियों से शादी करने की बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों में परिलक्षित होती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े केवल रिपोर्ट किए गए मामलों को दर्शाता हैं और वास्तविक संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। वर्तमान रिट याचिका में निकाले गए 2016 एनसीआरबी डेटा को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

अपहरण और विवाह के लिए दुर्व्यवहार का उद्देश्य												*कुल बच्चे पीड़ित*		
6 साल से कम			*6 से 12 साल तक*			*12 से 16 साल तक*			*16 से 18 साल तक*					
पु.	म.	*कुल*	पु.	म.	*कुल*	पु.	म.	*कुल*	पु.	म.	*कुल*	पु.	म.	*कुल*
0	*139*	*139*	*0*	*666*	*666*	*0*	*6461*	*6461*	*1*	*9671*	*9672*	*1*	*16937*	*16938*

5. उन्होंने कहा कि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल 16,938 मामलों में से, एक पुरुष बच्चे के मामले को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में लड़कियों का अपहरण शामिल था। उनके अनुसार, वास्तव में चौंकाने वाली बात यह है कि शादी के उद्देश्य से छह साल से कम उम्र के 139 बच्चों का भी अपहरण कर लिया गया था। उनका कहना है कि 6-12 वर्ष के आयु वर्ग में अपहरण लड़कियों की

संख्या 666 थी और 12-16 वर्ष के आयु वर्ग में इस तरह के अपहरणों की संख्या 6,461 थी और 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के बीच अपहरण लड़कियों की संख्या 9,671 थी।

6. वह यह भी बताते हैं कि 2011 की जनगणना के गर्भ धारण करने के आंकड़ों से पता चलता है कि पंद्रह साल से कम उम्र की कई लड़कियों को बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि पंद्रह वर्ष से कम आयु की 29,714 बालिकाएँ थीं जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और पंद्रह वर्ष से कम आयु की 29,130 बालिकाएँ थीं जिन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया।

7. वह निवेदन करते हैं कि बाल यौन दुरुपयोग के सभी मामलों में, जिनमें वैवाहिक बलात्कार की शिकार बच्चों से संबंधित मामले भी शामिल हैं, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान एक विशेष कानून होने के नाते पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 क के आधार पर भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) पर अध्यारोही रहेंगे।

8. वह अंत में निवेदन करते है कि वैवाहिक बलात्कार के नाबालिग पीड़ित नाबालिग होने की अवधि के दौरान शिकायत दर्ज करने या दूसरों को अपराध के बारे में सूचित करने में समर्थ नहीं हो सकती हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि वैवाहिक बलात्कार के नाबालिग पीड़ितों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

('पीसीएम अधिनियम') की धारा 3 (3) के अनुरूप बीस साल की उम्र तक शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए। उक्त धारा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"3. **बाल-विवाहों का, बन्धन में आने वाली पक्षकार के, जो बालक है, विकल्प पर शून्यकरणीय होना-** (1) प्रत्येक बाल विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न किया गया हो, अनुबंध करने वाले पक्ष के विकल्प पर अमान्य* होगा जो विवाह के समय एक बच्चा थाः.....
> (3) इस धारा के तहत याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है, लेकिन बालिका द्वारा याचिका दायर करने से पहले व्यस्क होने के दो साल पूरे हो जाए।

<u>प्रत्यर्थीगण की ओर से तर्क</u>

9. भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता का कहती है कि उन्होंने वर्तमान रिट याचिका में गृह मंत्रालय से दं. प्र स. के सम्बन्ध में साथ-साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय से पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ('जेजे अधिनियम') के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों को पहले ही अभिलेख पर रखा है। वह प्रार्थना करती है कि उक्त टिप्पणियों को उसके तर्क के रूप में पढ़ा जाए। टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> ***<u>"माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र विचार द्वारा दायर रिट याचिका संख्या में गृह मंत्रालय द्वारा दायर एक संक्षिप्त जवाबी शपथ पत्र तैयार करने के लिए टिप्पणियां।</u>***

1. याचिकाकर्ता ने धारा 198 (6) को उस हद तक घोषित करने का आदेश देने की मांग की है जहां तक यह पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है, असंवैधानिक और अटके होने के लिए उत्तरदायी है, कि पोक्सो अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित धारा 19 को अधिनियम के तहत किए जा रहे अपराध की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है जो द.प्र.सं. की धारा 198 (3) के साथ पठित धारा 198 (1) के तहत लगाए जा रहे प्रतिबंधों को अध्यारोही करता है और आदेश दे द.प्र.सं. के प्रावधान 198 (6.) को *सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण संशोधन के लिए जिससे वैवाहिक बलात्कार के नाबालिग पीड़िताओं को पॉक्सो की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुरूप 20 साल की उम्र तक शिकायत दर्ज करने का लाभ देगा।*

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं. प्र. सं.) भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए सामान्य प्रक्रिया पर एक कानून है। हालाँकि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एक विशिष्ट मामले को नियंत्रित करने वाले कानून हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 विशेष रूप से कानूनी प्रावधानों के माध्यम से बच्चों के यौन उत्पीडन और यौन शोषण को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था। किशोर न्याय अधिनियम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए तैयार किया गया था जिन पर आरोप लगाया गया है और जो कानून का उल्लंघन करते पाए गए हैं और जिन्हें विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है।

3. लेक्स स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत के अनुसार विशेष कानून सामान्य कानूनों को निरस्त करता है। *यदि दो कानून एक ही तथ्यात्मक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, तो एक विशिष्ट विषय वस्तु (लेक्स स्पेशलाइजेशन) को नियंत्रित करने वाला कानून केवल सामान्य मामलों (लेक्स जनरलिस) को नियंत्रित करने वाले कानून को अध्यारोही करता है। "लेक्स पोस्टीरियर अलमनेट लेगी प्रायोरी" का सिद्धांत भी लागू हो सकता है कि नया कानून पुराने कानून को अध्यारोही करता है।*

4. नाबालिगों को दं. प्र. सं. के प्रावधानों से बचाने के लिए रिट दायर करने के याचिकाकर्ता के इरादे पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। दं. प्र. सं. के किसी भी प्रावधान को संशोधित या असंवैधानिक घोषित करना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो पॉक्सो अधिनियम और जेजे अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता पर अध्यारोही हो जाएंगे।

5. यदि बाद के चरण में आवश्यकता हो तो प्रतिनिधि अतिरिक्त शपथ पत्र दायर करने के लिए अनुमति चाहता है।"

10. प्रत्यर्थी-भारत संघ के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पी.सी.एम. अधिनियम की धारा 3(3) वैवाहिक बलात्कार की नाबालिग पीड़िताओं पर लागू नहीं होती है क्योंकि उक्त प्रावधान केवल बाल विवाह की अमान्यता से संबंधित है। वह यह भी बताती हैं कि *दं. प्र. सं.* की धारा 472 और 473 कुछ मामलों में सीमा की अवधि के विस्तार का प्रावधान करती है। उक्त धाराओं को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

*"**472. निरंतर अपराध** - निरंतर अपराध के मामले में, अपराध जारी रहने के समय के हर क्षण पर सीमा की एक नई अवधि शुरू हो जाएगी।*

***473. कुछ मामलों में सीमा की अवधि का विस्तार -** इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी न्यायालय सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है, यदि वह तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर संतुष्ट है कि देरी को ठीक से समझाया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।"*

न्यायालय का तर्क

ऐसे बच्चों की कोई अलग श्रेणी नहीं है जो वैवाहिक स्थिति में बलात्कार के शिकार हुए हों।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद और भारत संघ के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्राप्त उपरोक्त निर्देशों को पढ़ने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि पॉक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है जो बच्चों के यौन उत्पीडन और यौन शोषण के जघन्य अपराधों से व्यापक रूप से निपटता है। 2012 में इस अधिनियम के लागू होने से पहले, बच्चों के खिलाफ कुछ लैंगिक अपराधों पर भा.द.स. के तहत मुकदमा चलाया गया था।

12. नतीजतन, इस न्यायालय का विचार है कि बलात्कार के शिकार बच्चों के भीतर कोई अलग श्रेणी नहीं है जो विवाहित हैं और जो नहीं हैं।

13. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब कोई सामान्य कानून और एक विशेष कानून कुछ सामान्य पहलू पर कार्य करे जो विवादास्पद होता है, तो अपनाया गया और लागू किया गया नियम सामंजस्यपूर्ण निर्माण का होता है, जिसके द्वारा सामान्य कानून को विशेष कानून द्वारा उस हद तक निपटा जाता है कि निहित रूप से निरस्त कर दिया जाता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति लैटिन मैक्सिम ऑफ जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट में पाई जाती है अर्थात सामान्य कानून विशेष कानून के लिए उपज देता है यदि वे एक ही विषय पर एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। (*देखिएः* ***वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजस्थान बनाम बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड और एक अन्य, (2014) 8 एससीसी 319)।***

<u>पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित धारा 19 द.प्र.सं. की धारा 198(3) के साथ पठित धारा 198 (1) के तहत अधिरोपित प्रतिबंधों को हटा देगी।</u>

14. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका ***इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एन.आर. (2017) 10 एससीसी 800*** (ग) में भारतीय दंड संहिता के साथ पोक्सो अधिनियम का सामंजस्य स्थापित किया है और यह माना है कि भा.द.स. की धारा 375 के अपवाद 2 को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा। *किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ संभोग या यौन कृत्य, पत्नी की आयु अठारह वर्ष से कम न हो, बलात्कार नहीं है।*" उक्त निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> *"107.... इसलिए, हमारे पास बच्चों से संबंधित कानूनों की प्रणाली को सुसंगत बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है और भा.द.सं. की धारा 375 के अपवाद 2 को अब सार्थक रूप से पढ़ने की आवश्यकता है: "एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संभोग या यौन कृत्य, पत्नी की उम्र अठारह वर्ष से कम नहीं है, बलात्कार नहीं है। इस पठन के माध्यम से ही विवाहित बालिकाओं के लिए सामाजिक न्याय के इरादे और हमारे संविधान निर्माताओं की संवैधानिक दृष्टि को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सकता है और शायद प्रोत्साहन दिया जा सकता है।*
>
> *XXX XXX XXX*
>
> *197. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरी स्पष्ट राय है कि भा.दं.सं. की धारा 375 का अपवाद 2 जहां तक यह 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका से संबंधित है, निम्नलिखित आधारों पर निरस्त किया जा सकता है:-*

(i) यह मनमाना, मनमौजी, सनकी और बालिकाओं के अधिकारों का उल्लंघन है और निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित नहीं है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 का उल्लंघन है;

(ii) यह भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और;

(iii) यह पॉक्सो के प्रावधानों के साथ असंगत है, जो प्रबल होना चाहिए।

इसलिए, भा.दं.सं. सी. की धारा 375 के अपवाद 2 को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

"अपवाद 2.- किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य, जिसकी पत्नी 18 वर्ष की नहीं है, बलात्कार नहीं है।" हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस निर्णय का भावी प्रभाव होगा।

198. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संहिता की धारा 198(6) 18 वर्ष से कम उम्र की "पत्नियों" के बलात्कार के मामलों पर लागू होगी और संहिता की धारा 198(6) के प्रावधानों के अनुसार ही संज्ञान लिया जा सकता है।"

15. किसी भी स्थिति में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 42क विशेष रूप से प्रदान करती है कि किसी भी विसंगति के मामले में, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का विसंगति की सीमा तक ऐसे किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों पर अध्यारोही प्रभाव पड़ेगा। पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 क को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"42क. किसी अन्य कानून के अवमूल्यन में अधिनियम नहीं। *इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के*

अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे और किसी भी विसंगति के मामले में, इस अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी ऐसी कानून के प्रावधानों पर विसंगति की सीमा तक अध्यारोही प्रभाव पड़ेगा।"

16. नतीजतन, यह न्यायालय घोषणा करता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित धारा 19 द.प्र.सं. की धारा 198 (3) के साथ पठित धारा 198 (1) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को अध्यारोही करेगी। हालांकि, यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि उसने वर्तमान कार्यवाही में एक वयस्क महिला के 'वैवाहिक बलात्कार' के बड़े मुद्दे पर विचार नहीं किया है।

द.प्र.सं. की धारा 472 और 473 न्यायालयों को सीमा की अवधि बढ़ाने का अधिकार देती है

17. जहां तक सीमा की विस्तारित अवधि के लिए याचिका का संबंध है, इस न्यायालय का विचार है कि द.प्र.सं की धारा 472 और 473 न्यायालयों को सीमा की अवधि बढ़ाने का अधिकार देती है, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सीमा की अवधि के विस्तार की आवश्यकता है या देरी को ठीक से समझाया गया है। यह न्यायालय प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के साथ सहमत है कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 (3) बाल विवाह की शून्यता से संबंधित है और विवाहित नाबालिग बच्चों के बलात्कार के मामलों में शिकायत दर्ज करने की सीमा की अवधि का विस्तार नहीं करती है। तदनुसार, उपयुक्त मामलों में जहां नाबालिग पीड़िता समय के भीतर अपनी शिकायतें दर्ज

करने में सक्षम नहीं हैं, विचारण न्यायालय के पास सीमा की अवधि को बढ़ाने की शक्ति है, यदि वह उचित समझे।

18. उपरोक्त घोषणा और टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निपटान कर दिया जाता है।

न्या. मनमोहन

न्या. सौरभ बनर्जी

3 मई, 2023
केए/टीएस/एएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*